महोदय, राजघाट, कन्नौज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर सेतु बनाना स्वीकृत हुआ है। जिसे सेतु निगम द्वारा बनाना स्वीकार किया गया है। इस पुल के बन जाने से कन्नौज और हरदोई के बीच का मार्ग सुगम हो जाएगा और यहां का सम्पर्क राष्ट्रीय मार्ग (नेशनल हाईवे) से सीधा हो जाएगा। कन्नौज उत्तरी भारत की लम्बे समय तक राजधानी रही है और हिन्दुस्तान के इतिहास में उसका अनूठा एवं गौरवशाली स्थान रहा है। कन्नौज के ही राजा दिल्लु ने दिल्ली नगर को बसाया था, लेकिन उनका मुख्य नगर कन्नौज पूर्णतया उपेक्षित है, जबकि कन्नौज आज भी इत्र के व्यवसाय से विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। संबंधित अधिकारीगण इस पुल को तकनीकी कारण बताकर अन्यत्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार स्थान परिवर्तन से राजघाट पर पेन्टून (पीपों का पुल) बनाए रखने की आवश्यकता हमेशा के लिए रहेगी, जिसके रख-रखाव पर सरकार को जो लाखों रुपए प्रति वर्ष खर्च करना चालू रखना पड़ेगा और नए स्थान पर पुल बनने से पुल के दोनों ओर पुनः नई सड़क भी बनानी पड़ेगी। इससे सरकार को अधिकतम धनराशि तो व्यय करनी पड़ेगी, पुल बनाने का मुख्य उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा।

अतः सरकार से आग्रह है कि कन्नौज के नाम पर स्वीकृत पुल को कन्नौज में ही राजघाट पर गंगा नदी पर बनाने हेतु संबंधित अधिकारियों को अविलम्ब यथोचित निर्देश देने का कष्ट करें और स्थान परिवर्तन की योजना को किसी प्रकार से स्वीकृत न करने का कष्ट करें।

(v) Financial assistance to people affected by recent hail—storin in Gorakhpur (U.P.)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, गोरखपुर जिले में भयंकर ओलावृष्टि के कारण भीषण क्षति हुई है। ईंट के बराबर के आकार तक के ओले पड़ने के कारण हजारों मकान पूर्णतः नष्ट हो गए हैं और करोड़ों रुपये की फसल बरबाद हो गई है। आम की फसल भी नष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में किसानों के समक्ष भुखमरी का संकट उत्पन्न हो रहा है। अनेक लोग गृहविहीन हो गए हैं।

अतः सरकार से मेरी माँग है कि व्यापक पैमाने पर राहत कार्य आरम्भ किए जायें। लोगों को मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए तथा किसानों को एवं गरीब लोगों को भुखमरी से बचाने के प्रयत्न किए जायें और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किए जायें, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सके। साथ ही किसानों से हर प्रकार की वसूली तत्काल बन्द कर दी जाए और उन्हें छूट भी प्रदान की जाए।

(vi) Drinking Water Scheme from Rajasthan canal to solve drinking water problem in Rajasthan

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रान्त के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में पीने के पानी की समस्या भयंकर रूप से हैं।

राज्य सरकार अपने साधनों और केन्द्रीय सरकार की सहायता से पीने के पानी की समस्या को हल करने का अथक प्रयास कर रही है और काफी गाँवों में नलकूपों का निर्माण कर क्षेत्रीय ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के द्वारा पीने का पानी पहुँचा रही है।

मनुष्यों एवं पशुओं द्वारा नलकूपों को पीने का पानी के रूप में लगातार उपयोग

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

करने के कारण पानी का स्तर दिनों दिन गिर रहा है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये नल-कूप 15 वर्ष से 30 वर्ष तक भी नहीं चल सकेंगे और उनका पानी बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में भविष्य में इन थार के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां वर्षा बहुत कम होती है, पीने के पानी का संकट और बढ़ जाएगा और बढ़ी हुई आबादी को उन क्षेत्रों से हटाने का प्रश्न खड़ा हो जाएगा।

इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी का स्थाई हल राजस्थान नहर द्वारा ही हो सकता है।

अत: निवेदन है कि राजस्थान सरकार केन्द्रीय सरकार के सहयोग से राजस्थान नहर द्वारा रेगिस्तानी बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में महत्वपूर्ण नगरों एवं ग्रामों में पानी पहुंचाने की तुरन्त योजना बनाकर उक्त समस्या का स्थायी हल करने में सक्रिय सहयोग दे।

(vii) Inclusion of research on betel leaves in the 20-Point Programme and providing the needy betel leaf cultivators with interest free loans

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के 33 जिलों में से 23 जिलों में पान की खेती होती है। नालन्दा, नवादा, औरंगाबाद एवं गया में 1 हजार एकड़ में मगही पान उगाये जाते हैं और शेष 19 जिलों में विभिन्न किस्मों के पान जैसे—बंगला, बंगरा, कपूरी, साँची आदि की खेती 6890 एकड़ भूमि में होती है। अत: कुल 7890 एकड़ में लगभग साढ़े नौ लाख व्यक्ति पान की खेती से जीविका अर्जित करते हैं।

हर दृष्टि से पान-कृषक सीमान्त किसान हैं। एक परिवार तीन डेसीमल से लेकर एक एकड़ भूमि पर शोधकार्य न होने से पुरानी रीति से ही राम-भरोसे खेती कर अपना गुजारा करता है। गत तीन वर्षों से पान में ग्रेश का प्रकोप होना आरम्भ हो गया है। गत वर्ष तो मगही पान बिल्कुल नष्ट हो गया। अन्य फसलों की तरह पान की दवा और खाद की जानकारी के अभाव में पान-कृषक खेती को रोग से बचाने में असमर्थ हैं। इस शीत लहरी से बिहार में यदि दक्षिण भारत से पान नहीं आता तो पान का दर्शन भी दुर्लभ हो जाता।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि :

1. पान-कृषकों को राहत एवं पान की खेती के विकास—इसे बीस सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित कर मदद की जाय तथा पुन: खेती करने के लिये ज़रूरत मन्द परिवार को उसकी क्षमता और भूमि पर कब्जे के आधार पर कम से कम दो हज़ार और अधिकतम 20 हज़ार रुपये का सूद रहित ऋण दिया जाय।

2. पान की खेती के काम में आने वाले खर और बाँस जो जंगलों से उपलब्ध होते हैं, उसे पान-कृषकों को उनके संगठनों के माध्यम से रियायती दर मुहैया किया जाय।

3. बिहार में राजेन्द्र कृषि विश्व विद्यालय पूसा में पान पर शोध एवं अनुसंधान आरम्भ कराया जाय।

12.32 hrs.

FINANCE BILL, 1983—*Contd*

MR. DEPUTY-SPEAKER : We shall now take up General Discussion